पुन: अपने पुराने लघु-धंधों की ओर जाना होगा, गांधी जी के सिद्धांतों पर जाना होगा और हमें इस पर बैलेंस करना होगा कि एक तरफ हम हाइ-टैक की ओर जाएं क्योंकि आज विश्व बाजार का वैश्वीकरण हो चुका है । हमें एक तरफ उसे भी अपनाना है और दूसरी तरफ अपने धरातल पर रहते हुए, अपने ग्रामीणों को देखते हुए - दोनों का तालमेल करते हुए कोई ऐसी रणनीति अपनानी होगी ताकि हमारे नौजवान रोजगार पा सकें । हमारी बहनों को काम मिले ताकि वे अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सकें । देश को अच्छे नौजवान दे सकें, पढ़े-लिखे नौजवान दे सकें और देश को आगे बढ़ा सकें । मैं इन्हीं शब्दो के साथ आप के विधेयक का स्वागत करती हूं, समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA
THE IRON AND STEEL COMPANIES (AMALGAMATION AND TAKEOVER LAWS) REPEAL BILL, 2000

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Iron and Steel Companies (Amalgamation and Takeover Laws) Repeal Bill, 2000, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 28th July, 2000."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE ERADICATION OF UNEMPLOYMENT BILL, 1996 - contd.

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं. । इस के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में जो पहला वाक्य प्रयोग किया गया है, वह इस प्रकार है In rural areas schemes have to be implemented in such a way that work is available throughout the year to the rural youth उपसभाध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि आज देश के गांवों में गांवों के लोगों के लिए जो काम होते हैं, सात-आठ साल पहले के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, वे यह बताते हैं कि जो काम करना चाहते हैं उनको भी पूरे साल में बहुत कम काम मिलता है - पुरुष जो काम करना चाहते हैं उनको 365 दिन में से 165 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता और हमारी बहनें, जो काम करना चाहती हैं गांवों में, उन बहनों को एक साल में 135 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता । परिस्थिति यह है कि सारे देश में हमारी जो बेरोज़गारी की समस्या को लिखित रूप से ज्ञात कराने की जो ऐम्प्लॉयमेंट ऐक्सचेंज की व्यवस्था है, उसके आंकड़े यह बताते हैं कि देश में करीब 5 करोड़ हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं । लेकिन हम अगर पूरे देश को और हमारा देश गांव प्रधान देश है, इसको ध्यान में रखकर देखें तो बेरोज़गारों की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास होगी । बेरोज़गारी के साथ

जुड़ी हुई जो समस्या है, वह गरीबी की समस्या है । हमारे वित्त मंत्रालय के पास 1993-94 के बाद पिछले 6 साल के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यू0एन0डी0पी0 की जो रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया है कि 1991 से 1998 तक आर्थिक उदारीकरण, खानगीकरण और वैश्वीकरण का जो हमारा युग चला, इसके कारण हमारी बेरोज़गारी बढ़ी । देश में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं और इन 40 करोड़ लोगों का जब ऐनेलाइस किया गया कि उनमें कितनी गरीबी है तो पता चला कि देश में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50 पैसे से ज्यादा है लेकिन 3 रुपए से कम है, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 3 रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 रुपए से कम है, 10 करोड़ और लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 रुपए से ज्यादा है और 40 करोड़ लोग 2,444 रुपए से नीचे एक साल की आमदनी रखने वाले हैं और इस हालत में हमारे भारत के नागरिक सन् 2000 के साल में हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ऑब्जेक्ट्स में जो आपने बताया, उसको यदि हम सही तरह से ध्यान में रखें तो जो आज की परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखना होगा । 1991 में इस देश में करीब 15 करोड़ हैक्टेयर जमीन पर खेती होती थी । 1998-99 में भी खेती में जो ज़मीन काम में लाई जाती थी, वह बढ़ी नहीं, उसी 15 करोड़ हैक्टेयर ज़मीन पर ही खेती होती रही । 1991 में खेती पर हमारे गांव और देहातों के जो लोग आश्रित थे, उनकी संख्या करीब 18 करोड़ थी, लेकिन खेती पर आश्रित इन लोगों की संख्या 1998-99 में बढ़कर 22 करोड़ 20 लाख हो गई। ज़मीन उतनी ही रही लेकिन 4 करोड़ और भारतीय नागरिक खेती में जुट गए । परिस्थिति यह हुई कि खेती में से जो आमदनी होती थी, उसमें भी कमी आने लगी । दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में आज 4 करोड़ हैक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो खेती के लायक है लेकिन उसको खेती के काम में लाया नहीं जा सका । एक हैक्टेयर ज़मीन अगर सही तरीके से खेती के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको सही खाद मिले, उसको दवा मिले, उसको जितना चाहिए उतना पानी मिले तो एक हैक्टेयर ज़मीन 20 हजार रुपए की आमदनी देने की क्षमता रखती है ।

महोदय, मैं आपके सम्मुख एक उदाहरण रखना चाहूंगा । महोदय, गत वर्ष हमारे गुजरात में अकाल था । जिस किसान ने अपनी जमीन पर कपास बोया था, एक हैक्टेयर जमीन पर कपास बोने का सारा खर्चा जो आता है खाद का, बीज का, ऐग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स का, वह करीब 6,000 रुपए आता है । इस एक हैक्टेयर जमीन से उसको गत वर्ष जो आमदनी मिली, कपास का जो उत्पादन हुआ, वह करीब 4,000 रुपए मूल्य का हुआ यानी उस किसान ने जो कैपिटल इन्वैस्टमेंट किया था, उस पर उसको 2,000 रुपए का नुकसान हुआ ।

महोदय, मैं उससे पिछले वर्ष की बात भी आपको याद दिलाना चाहूंगा । उस साल गुजरात में बारिश अच्छी हुई थी, समय से हुई थी, जब बारिश रुकनी चाहिए थी, तब रुकी थी और फिर जो दूसरी और तीसरी बारिश होनी चाहिए, वह हुई थी । यानी जितना पानी इस कपास की खेती के लिए चाहिए था, उतना पानी उसे मिला । ऐसी हालत में वही जमीन, वही खाद, वही बीज, वही ऐग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, वही दवाएं, इन सब से करीब 50-51-52 मन प्रति हैक्टेयर कपास का उत्पादन हुआ और उस किसान की आमदनी हुई करीब 25000-26000 रुपए । यानी 6,000 रुपए की कैपिटल इन्वैस्टमेंट पर 6-7 महीने में चार गुना आमदनी होती है ।

महोदय, देश में पिछले 52-53 सालों में हमारे पास जो पानी उपलब्ध है, उस पानी की उचित व्यवस्था हम नहीं कर पाए । देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें अकाल का सामना करना पड़ता है । जैसा गत वर्ष राजस्थान और गुजरात में हुआ । इन दोनों राज्यों को अकाल का सामना करना पड़ा । क्या आज भी हम यह नहीं सोच सकते कि पूरे देश में पानी के जो स्रोत उपलब्ध हैं, उन पानी के स्रोतों की जहां-जहां आवश्यकता है, वहां हम उन्हें पहुंचाएं ? उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी पर कैपिटा पानी की आवश्यकता 300 लीटर से ज्यादा नहीं है । इसमें सिंचाई आ जाती है, उद्योग आ जाते हैं और डोमेस्टिक कंज़म्पशन भी आ जाता है । देश में जो ऐसे राज्य हैं, जिनको स्कैंटी रेन ऐरिया बोलते हैं, जैसे गुजरात है, जहां बारिश कम होती है, वैसे प्रदेशों को अगर हम ध्यान में रखें तो भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति करीब 8000 लीटर पानी बारिश का आता है लेकिन उसमें से 7,700 लीटर पानी समुद्र में बहकर चला जाता है । इस पानी का हम आज तक उपयोग नहीं कर पाए। अगर हमने यह पानी अपने किसानों को उपलब्ध करा दिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती, बेरोजगारी की नौबत नहीं आती, किसानों के बच्चों को गांव छोड़कर शहर जाने की नौबत नहीं आती ।

महोदय, देश में जो भूमि हम कृषि के लिए उपयोग में लाते हैं, आज़ादी के 53 साल के बाद आज भी उस भूमि में 45 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था हम नहीं कर पाए । क्या यही व्यवस्था हम आगे आने वाले सालों में भी चलाते रहेंगे ? क्या हमें रेन गॉड पर ही भरोसा करके चलना होगा?

महोदय, जैसी परिस्थिति पानी में है, खेती के लायक जमीन में है, वैसी ही परिस्थिति आज पशु धन में भी है । हमारे देश में आज 28,000 करोड़ पशु धन है । मैं "पशु धन" शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करते हैं । क्या हम गलत तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करते?

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक गौशाला का प्रमुख हूं। जो पशु दूध नहीं देते उनको लोग हमारे यहां छोड़ कर चले जाते हैं। जिसको हम ड्राउट एनिमल बोलते हैं। ड्राउट एनिमल का जो डंग होता है उसको हम बॉयो गैस प्लांट बनाकर के, उसको हम खाद के नाते उपयोग में लाते हैं। और उसके साथ-साथ बिजली का उत्पादन करके आर्थिक दृष्टि से इस पशु धन का उपयोग क्या हम नहीं कर सकते हैं? दूध देने वाली जो गाय हमारे पास हैं, मेरे खुद का अनुभव भी है जिसे मैं आपको बतला रहा हूं। हमारी गौशाला में 5 गाय हैं। सार्वजनिक संस्था होने के कारण उसमें तो रख रखाव ऐसा होता है कि औसतन एक गाय पांच लीटर दूध देती है। इस प्रकार 25 लीटर दूध मिलता है। हम दस रुपए लीटर में दूध बेच देते हैं। हमको इनसे 250 रुपए एक दिन में आता है और इन पांच गायों का खर्च सिर्फ 75 रुपए से ज्यादा नहीं आता। यानी जो चारा हम इनको देते हैं, इनको जो और पौष्टिक खुराक देनी पड़ती है, पहले हमारे यहां तो यह व्यवस्था थी कि हमारे पशु धन के लिए गोचर नीम करके हमारे पशुओं के लिए इस चारे का खर्च भी नहीं आता था। गांव की अपनी खुद की आर्थिक व्यवस्था थी, गांव में खुद अपना आर्थिक एकम बना हुआ था, किसी को किसी पर आधार नहीं रखना पड़ता था। इस बात को हम भूल गए, हमारे पशु धन का उपयोग नहीं हो रहा है। ...**(समय की घंटी)**... उपसभाध्यक्ष जी, मैं दो-तीन मिनट लूंगा।

अलकबीर का कत्ल खाना चल रहा है, पशुओं का कत्ल खाना चल रहा है। पिछले पांच साल में इस अलकबीर के कत्ल खानों में जितने भेड़ों के कत्ल करने का आयोजन किया गया उससे मांस की जो आमदनी हुई वह 20 करोड़ की हुई। लेकिन अगर इन भेड़ों को पाला होता तथा उनसे अगर हमने ऊन ली होती तो आमदनी 76 करोड़ रुपए होती। तो क्या पसंद करना चाहिए हमको? तो क्या इस देश में ऐसे कत्ल खाने चलाए जाने चाहिए? आर्थिक दृष्टि से भी यह कत्ल खाने चलाना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। भैंसों के कत्ल की जो संख्या वहां पर बताई गई तथा उससे जो मांस की आमदनी होगी वह करीबन 90 करोड़ होगी लेकिन उन भैंसों से जो दूध मिलेगा, डंग मिलेगा तथा उन भैंसों को जो हम खेती के काम में लाएंगे उससे आमदनी 226 करोड़ रुपए की होगी। ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि हमारे देश के पशु धन का उपयोग योग्य तरीके से करने में हम विफल रहे और इसके कारण गांवों में यह बेरोजगारी की समस्या खड़ी हुई, गरीबी की समस्या खड़ी हुई। इस स्थिति में हमें नए सिरे से सोचना होगा।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा। इस देश में आज जो नाणांकीय संस्थाएं हैं वह नाणांकीय संस्थाएं आर्गनाइज्ड सैक्टर में जो भी धन उपलब्ध करना चाहिए वह कराते हैं। लेकिन इस देश का नौजवान, इस देश की बहनें इस देश में स्वरोजगार के क्षेत्र में जाने वाला हमारा नौजवान इसको कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं कराता और इस क्रेडिट गेप को कोई पूरा नहीं करता। जो वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े आज हमारे पास उपलब्ध हैं वह यह बतलाते हैं कि देश में करीबन 90 हजार से एक लाख करोड़ का ऋण हमारे नवयुवक और नवयुवतियों को देना चाहिए लेकिन हमारी वित्तीय संस्थाएं दस हजार करोड़ से ज्यादा ऋण हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों को नहीं उपलब्ध कराते। जबकि परिस्थिति यह है कि इनके पास कुशलता है, इनमें काम करने की हिम्मत है, इनमें काम करने की दृष्टि है लेकिन वित्तीय संसाधन इनके पास नहीं होने के कारण वे स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं करा पाते, स्वरोजगार में नहीं जुट सकते।

इस परिस्थिति के कारण देश में बेकार नौजवानों की, नवयुवतियों की फौज खड़ी होती जा रही है। उपसभाध्यक्ष जी, देश में खनिज के बहुत संसाधन हैं। हमारे देश में मिनरल रिसोर्सेस हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनियाभर के जितने भी देश हैं उन में हमारे जैसे खनिज संसाधनों की विविधता और उपलब्धता नहीं है। क्या इस देश के खनिज को हम सही मायने में उपलब्ध करके उसका उपयोग आर्थिक दृष्टि से करते हैं? हमारा जो सौराष्ट्र का इलाका है वहां पर बाक्साइट मिलता है। लेकिन हम बाक्साइट को पानी के मूल्य पर चाइना को बेच रहे हैं। हम उसे अपने उपयोग में नहीं ला रहे हैं। बाजार में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में इसका उपयोग करके हम अपने नौजवानों को रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, इसके लिए हमें कोई योजना बनानी चाहिए। हमारे देश में जितने भी कुदरती संसाधन हैं, उनका हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण टेक्नालाजी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जो हमें करना है वह हम जरूर करें। लेकिन हमारे जो गांवों में, देहातों में, शहरों में पिछड़े इलाके हैं, अगर उन्हें ऊपर उठाने के लिए यहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं तो हमारे जो कुदरती संसाधन हैं, हमें उनका उपयोग करना पड़ेगा। हमारा जो टाइनी सैक्टर है, हमारे जो परम्परागत उद्योग हैं, हमें उन्हें ध्यान में रखकर जो भी हमारी आवश्यकता है, उसके अनुसार उनको पूरा करना होगा तभी हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है उसका समाधान ढूढ़ने में हम सफल हो पायेंगे। धन्यवाद।

*SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Vice Chairman Sir, this is a very important Bill. I welcome and support this Bill which seeks to provide for employment and resources for self employment to all adult citizens for eradication of unemployment from the country and for matters connected there with. Through this Bill you as a mover of this Bill have highlighted the seriousness of this problem and brought it to the notice of this August house. This is highly appreciable Sir.

Sir, crores of people have sacrificed so much to acquire freedom for our country. Our freedom fighters drove away the Britishers ruling our country and introduced democratic system of governance, created the Rajya Sabha and the Lok Sabha so that we could make optimum use of our resources and create employment opportunities for each and every citizen of our country and see that every individual leads a happy and contented life.

Sir, we have been discussing about inclusion of right to work in our constitution. I remember we had a long and serious discussion on this issue. Whatever may be the reason the fact remains that we were unable to include right to work in our constitution. Even now it is not too late, Sir. I submit to all the intellectuals and all the political parties that right to work is very essential for our country and the sooner it is included in our constitution, the better it would be. Unfortunately, we are not giving it the priority it deserves. All successive political parties coming to power have given it fourth, fifth or sixth priority and definitely not the first priority. That is why I request and humbly submit sir, that right to work needs to be included in our constitution.

Sir, in our country unemployment problem is growing rapidly day-by-day. Most of us belong to villages. We all know there are many people in villages who depend on handicraft. But now the blacksmith, the potter, the carpenter, the washerman, the barber have all lost their source of livelihood. As we all know that Handloom weavers who suffered a lot and when driven to the brink of starvation had no option but to commit suicide. Sir, in villages also there were people who earned their living by entertaining the common public. The advent of Cinema has rendered them jobless. The result is the galloping unemployment problem which in turn has given

---

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

rise to the incidents of dacoity, robbery, murders and terrorism. So now there is a threat to the Law and order situation of our country. Sir, to improve the law and order situation, we could recruit people in the police department but that also cannot solve the problem as the situation has turned very grave.

Sir, with a heavy heart I am submitting through you that when the situation is so grave and people are forced to commit suicide due to the problem of unemployment, here we are talking of idiologies, policies and different governments. Sir, this is not a problem of any single political party or leader or government but of each and every individual of our country. If we have to blame someone we have to blame every one and not just a ruling party, or a Chief Minister or the Prime Minister or the concerned minister, or the Parliamentarians. We all have to share the responsibility and try to find out a solution to this serious problem rising above party politics. Sir, as far as agriculture is concerned, a number of changes have taken place. We have modern equipment now even for transplanting, harvesting and threshing activities. This has led to an increase in the unemployment problem. Our present Labour Minister also agrees on this point. It becomes our responsibility to create jobs for all those who have been deprived of their source of livelihood. Sir, we all know that industries are closing down. Whatever we may say or give reasons for it, the fact remains that the number of sick units are increasing. This has also contributed to the problem of unemployment as many factory labourers are virtually on the streets.

Sir, next are government organizations which can provide employment opportunities to the people. But then we all know that these organizations are facing the problem of surplus staff. With the Information Technology, spreading fast all over the world a single machine is able to do the job of ten or twenty or even fifty individuals. By adopting the modern methods of the latest Information Technology we have deprived many citizens of employment opportunities. The research conducted in Andhra Pradesh says that there is a surplus of one lakh sixty thousand workers. The government organizations do not fill up the vacancies even after the retirement of an employee or if an employee expires during his service or resigns his job. This is not the problem of the State Governments alone but

also of the Central government. The vacancies are not filled up on time because the people already do not have enough work to do.

Sir changes should be brought in our education system also. When there is an advertisement in the newspaper for a job we find that every educated individual applies for it.

Sir, I am half way and you have to be kind enough to me. People are availing forty minutes and thirty minutes.

The educated are not getting the jobs. Now those people who are educated in the latest Information Technology & Computer Science are getting jobs. But then in a year or two even these people would have to be told that there are no vacancies as again we are going to face the problem of surplus manpower.

The Centre and also the State governments are trying to create more job opportunities through rural and Urban Development departments. Shri Rajiv Gandhi once said that from a single rupee spent for the welfare of the poor the beneficiaries receive only fifteen paise and the rest of the money goes to middle men. Sir, the situation remains the same even today and we all have to accept this fact because we are all witnessing it. So, through this what I want to convey is that our policies are not reaching the targeted sections and so it is necessary that we take enough care in implementing the policies adopted for tackling the unemployment problem. Let us take, for example the various schemes launched by the Khadi and village industries commission (KVIC). I am sorry to say Sir, that very few people are aware of these schemes. Only such educated people know about these schemes who can fill up the application forms for jobs. The poor and uneducated have not been benefited by these schemes.

Now, we are in the age of Globalization and Liberalization. Whichever party has introduced it, be it BJP or Congress or any other party we have to accept it in order to keep pace with other countries of the world.

We will have to be part of Globalization and liberalization and this is the reality. But this has to be beneficial to the common man also. This is also contributing to the problem of unemployment. Yesterday while

answering a question our Labour Minister said about the increase in the GDP. He admitted that, Decreasing trend has been observed in respect of agriculture, forestry fishing and mining. I am happy that GDP in increasing. But as our labour Minister mentioned about decreasing trend in agriculture, forestry fishing and mining on which ninety percent of our population is depending only 10 percent or 15 percent may be different.I agree with the minister that there is an upward trend in GDP and development but at the same time it shows that ninety percent of the population is facing the unemployment problem. Another important issue which I want to highlight and which each one of us has to think about the well being of S.Cs, S.Ts. B.Cs. and women who also contribute in creating. wealth for our country. We have introduced the Reservation Policy in 1952 in our constitution. Justice should be done to them also. I am not against Globalization or liberalization but I want to know what is going to be the fate of the poor, the S.Cs. and S.Ts. of our country. In the wake of Globalization and liberalization preference is given to privatization. That is fine. But the government cannot get away from its responsibility towards our society, our country and the down trodden. People born in India, have made optimum use of our country natural resources for their education and for acquiring knowledge and have built up big industrial Houses. Now they have started exploiting the poor and the down trodden while for themselves they are minting money. There is a need to protect the interests of the down trodden. The millionaires like TATAs, BIRLAs, SINGHANIAs and DALMIAs have set up huge industries. Did they do it with their ancestral property? No. They have taken loans from IDBI, IFCI, ICICI etc.Whose money is it? They borrow from banks. Where does this money come from? It belongs to the people of this country. It belongs to those labourers who work hard for this nation. The benefits of the policies and principles of Social Justice and social security upheld by the nation should percolate down to each and every individual of this country including S.Cs. S.Ts. and B.Cs. They should not fall prey to the vagaries of privatization. It is time for the government to wake up. Since the government is adopting the policy of disinvestment in government and public sector units and encouraging private sector by providing crores of public money through different financial institutions, the government should pass a law to protect the interest of the common man including S.Cs., S.Ts. or B.Cs in private sector jobs.

[VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) in the Chair]

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): I think you are moving towards the conclusion.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: There are four problems which need to be addressed in our country rising above party politics and individual interest. We may adopt any number of programmes and make laws but unless and until we solve these four problems our country can never flourish. In this way we will be doing injustice to our country and harm the national interest. The four areas, which need to be given top priority are Population Control, Protection of environment, literacy programme creating employment opportunities.

These are the four items we will have to concentrate on and these are the only solutions for the nation, for the country, to make ourselves above others. Thank you very much Sir.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Sir, now we came to know he is one of the greatest orators of Andhra Pradesh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : Yes. Congratulate him.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है, इसको इस सदन के माननीय सदस्य भाई सुरेश पचौरी जी यहां लाए हैं. इस विधेयक के आधार पर सरकार को संविधान में संशोधन करके अतिशीघ्र एक विधेयक लाना चाहिए। ताकि देश के सामने जो बेरोजगारी की भीषण और विकट समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सके। इस समस्या के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे कानून और व्यवस्था की समस्या हो, आतंकवाद की समस्या हो, चाहे इस देश में मादक द्रव लाने वाले युवकों की समस्या हो, चाहे कृषि पर आधारित देश होने पर भी उसमें पैदा हुई बेरोजगारी की समस्या हो। इनको ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो यहां इतनी समस्याएं है कि यदि देश को आगे ले जाना है, स्वावलंबी बनाना है, देश का बंटवारा नहीं करना है, देश को सुरक्षित रखना है तो इन समस्याओं के लिए हमें कोई न कोई कदम उठाने चाहिएं नहीं तो देश की हालत भयंकर बन जाएगी। आज चाहे कोई शिक्षित या अशिक्षित हो, चाहे कृषि में लगा बेरोजगार हो, शिक्षित जो डिग्रियां ले रहे हैं, चाहे वह डॉक्टर बन गया हो या इंजीनियर बन गया हो या चाहे उसने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर ली हो, आज शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके सामने रोजगार का कोई साधन नहीं है । आज देश में यह स्थिति हो रही है कि लोग पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। यहां से शिक्षा प्राप्त करके दूसरे देशों में लोग रोजगार ढूंढ रहे है। इस स्थिति से निपटने के लिए यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया...(व्यवधान)...

5.00 P.M.

श्री ब्रतीन सेनगुप्त (पश्चिमी बंगाल) : तब यह कदम तुमने क्यों नहीं उठाए ?

श्री मूल चंद मीणा (राजस्थान) : डिस्कस करने की बात नहीं है । उस समय कदम उठाए गए । देश की आजादी के समय नेहरू जी ने यह सोचकर लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन.चतुर्वेदी) : मीणा जी, एक सैकिंड के लिए रुक जाएं । मैं हाउस का सैंस ले लूं । पांच बज रहे हैं ।

श्री सोलीपेटा रामचन्द्रा रेड्डी : सर, वे भी कंटीन्यू करना चाहते हैं, हम भी कंटीन्यू करना चाहते हैं।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI T.N.. CHATURVEDI): Hon. Members, now, we have to decide on the Calling Attention. (Interruptions) Mr. Meena can resume his speech.. *(Interruptions)* on the 11th. On the Calling Attention, I have to take the sense of the House. Should we continue with Mr. Pachouri's Calling Attention?

SOME HON. MEMBERS: We may adjourn for today.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): If this is the sense of the House . . . *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: If Mr. Pachouri is ready, there is no objection from our side.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, on Monday we have to take up the discussion on the disinvestment policy. *(Interruptions)*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : In that case, we will have to forgo the lunch break.

श्री सुरेश पचौरी : सर, इस सदन में ऐसा भी हुआ है कि जिस दिन शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ है उसी दिन कालिंग अटेंशन भी हुआ है ।

SHRI O. RAJAGOPAL: We will take it up on the next working day.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, on the next working day, we have to take up the Disinvestment policy.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): कालिंग अटेंशन भी हो सकता है ।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Both can be taken up on the same day. Both the matters are important; so they should be disposed of at the earliest. The House stands adjourned.... *(Interruptions)*

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): जैसा उपसभाध्यक्ष महोदय चाहें ।

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): Sir, the Calling Attention is on an important point and it should be cleared and deliberated in the House as quickly as possible. *(Interruptions)* I want to know on which date the Chairman would allow the matter to be taken up.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): On Monday.

SHRI T.R. BAALU: Sir, on Monday, after the Question Hour, I have to go to the Lok Sabha.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): No; it will be taken up after the Question Hour.

SHRI T.R. BAALU: I have to go to the Lok Sabha after the Question Hour. So, I will not be able to . . . *(Interruptions)*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : If it is not possible on Monday, then . . .*(Interruptions)*

SHRI T.R. BAALU: If the House agrees, it can be taken up on Monday. I will tell the Parliamentary Affairs Minister. And if the Minister agrees, it is okay.

quite accommodating. I won't say 'pliable'. He is quite accommodating. So, he will work it out. The House stands adjourned till 11.00 a.m., on Monday.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock, till eleven of the clock on Monday, the 31st July, 2000.